RNI No. RAJHIN/2001/05699

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

www.hellosarkar.com

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोनः 0141-2202717
मोः 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

वर्ष-25 | अंक-261 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, सोमवार 25 मई, 2026 | पृष्ठ-4 | मूल्यः 2.50

पेट्रोल-डीजल में फिर लगी आग, आधी हुई ट्रकों की आवक, हर चीज के बढ़े दाम

हैलो सरकार न्यूज

उदयपुर. पेट्रोल-डीजल के दामों में एक बार फिर हुई बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पहले से महंगाई की मार झेल रहे शहरवासियों के लिए अब रसोई चलाना और मुश्किल होता जा रहा है। डीजल की कीमत बढ़ने और कई राज्यों में किल्लत के कारण ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर मंडियों में खाद्यान्न, फल-सब्जी और रोजमर्रा के सामान की आवक पर पड़ा है।

रोजाना 50 से 60 ट्रकों से आने वाला माल घटकर 20 से 30 ट्रकों तक सिमट गया है। लंबी दूरी के ट्रक या तो देरी से पहुंच रहे हैं या फिर माल लेकर आने से कतरा रहे हैं। इसका असर अब हर घर की रसोई और हर बाजार की कीमतों में दिखाई देने लगा है।शनिवार सुबह छह बजे से पेट्रोल 93 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल अब 110.66 रुपए और डीजल 95.80 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। साथ ही परिवहन लागत बढ़ने से दाल, चावल, तेल, शक्कर, फल और सब्जियों तक के दाम तेजी से ऊपर जाने लगे हैं।

ट्रांसपोर्टरों ने बढ़ाया भाड़ा

व्यापारियों का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमत और कई राज्यों में सीमित सप्लाई के कारण ट्रांसपोर्टरों ने भाड़ा 15 से 25 हजार रुपए तक बढ़ा दिया है। इसका असर सीधे बाजार पर पड़ रहा है।

तेल व्यापारी अनिल जैन ने बताया कि गुजरात से आने वाली

गाड़ियां अब 7 से 8 दिन में पहुंच रही हैं। बढ़े हुए भाड़े के कारण तेल के प्रति टीन पर 100 से 150 रुपए तक का असर पड़ा है।

चीनी व्यापारी हंसराज पोखरना ने कहा कि सूरत और नवसारी से आने वाली गाड़ियों की संख्या में भारी कमी आई है। भाड़ा बढ़ने से चीनी के भाव में करीब 150 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई है।

श्री उदयपुर दाल-चावल व्यापार संघ के महामंत्री राजकुमार चित्तौड़ा ने बताया कि जयपुर और जोधपुर से आने वाले ट्रक अब पूरा लोड नहीं मिलने तक रवाना नहीं हो रहे। पहले 24 घंटे में माल पहुंच जाता था, अब आठ से दस दिन लग रहे हैं। इससे दाल और चावल के दाम 5 से 7 रुपए किलो तक बढ़ गए हैं। खाद्यान्न व्यापारी गणेशलाल अग्रवाल ने कहा कि किसानों से पहले ही कम माल आ रहा था, अब ट्रकों की कमी ने स्थिति और बिगाड़ दी है। गेहूं में भी करीब 150 रुपए प्रति क्विंटल तक तेजी आ चुकी है।

आम से आलू तक सब महंगे

फल व्यापारियों के अनुसार सबसे ज्यादा असर फलों और बाहर से आने वाली सब्जियों पर पड़ा है। फरूट व्यापारी हेमंत अछवानी ने बताया कि इस समय आम का सीजन होने के बावजूद पर्याप्त आवक नहीं हो पा रही। हैदराबाद, विजयवाड़ा और तिरुपति से आने वाले आम पर 20 से 25 हजार रुपए अतिरिक्त भाड़ा लग रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र से आवक लगभग ठप है। हर साल इस समय आम सस्ते हो जाते थे, लेकिन इस बार लगातार तेजी बनी हुई है।

श्री सब्जी फरूट व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश खिलवानी ने बताया कि पहले आलू, प्याज और लहसुन की 12 से 15 गाड़ियां आती थी, जो अब घटकर 7 से 8 रह गई हैं। होलसेल में 2 से 3 रुपए और रिटेल में 4 से 5 रुपए किलो तक बढ़ोतरी हुई है। नासिक और यूपी से आने वाले आलू-प्याज की आवक कम हुई है।

पेट्रोल-डीजल के नए भाव

ईंधन 22 मई 23 मई बढ़ोतरी
पेट्रोल 109.73 110.66 0.93
डीजल 94.89 95.80 0.91
स्पीड/पावर पेट्रोल 119.37 120.31 0.93--

असर एक नजर में

मंडियों में ट्रकों की संख्या आधी हुई

दाल-चावल 5 से 7 रुपए किलो महंगे- तेल के टिन पर 100 से 150 रुपए असर

चीनी में 150 रुपए प्रति क्विंटल तेजी- फल-सब्जियों के दामों में लगातार उछाल

रसोई का मासिक बजट बुरी तरह प्रभावित

महिलाओं की पीड़ाहर हफ्ते कीमतें बदल रही हैं। तेल, दाल और सब्जियों के बढ़ते दामों ने घर का पूरा हिसाब बिगाड़ दिया है। बच्चों की जरूरत और रसोई के खर्च में संतुलन बैठाना मुश्किल हो गया है।

तरुणा नागदा, गृहिणी

बच्चों की पढ़ाई, बिजली बिल और रसोई के खर्च के बाद बचत खत्म हो गई है। महंगाई अब सीधे मध्यमवर्गीय परिवारों की जिंदगी और भविष्य की योजनाओं पर असर डाल रही है।

पिंकी चित्तौड़ा, कामकाजी महिला

हर बार पेट्रोल-डीजल महंगा होता है तो बाजार में हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। अब फल और अच्छी सब्जियां खरीदने से पहले कई बार सोचना पड़ता है।

कॉकरोच जनता पार्टी' के नाम पर आपके साथ हो सकता है बड़ा धोखा, पुलिस ने जारी की चेतावनी

हैलो सरकार न्यूज

भरतपुर। सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों 'कॉकरोच' ऐसा शब्द बन गया है, जिसने रातों-रात देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक हलचल मचा दी है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) नाम से बने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलोअर्स की बाढ़ आ गई है। हर रील को औसतन 21 लाख लोग देख रहे हैं और युवाओं में इसे लेकर जबरदस्त क्रेज दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वायरल ट्रेंड के पीछे अब साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं।

पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सीजेपी के नाम पर अनजान लिंक भेजकर लोगों को ठगने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। साइबर अपराधी वाट्सऐप, मैसेंजर और एसएमएस के जरिए 'कॉकरोच पार्टी जॉइन करें' जैसे लिंक भेज रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यदि किसी ने बिना सोचे-समझे ऐसे संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर दिया तो उसका बैंक खाता मिनटों में खाली हो सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया के ट्रेंड और वायरल क्रेज में बहकर किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। कोई संदिग्ध मैसेज या लिंक मिले तो उसे तुरंत डिलीट कर दें और जरूरत पड़ने पर साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।

फिर आया कॉकरोच इज बैक

दरअसल, 21 मई को सीजेपी का पुराना एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। उस समय अकाउंट पर 1.93 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। अकाउंट बंद होते ही संगठन ने नया अकाउंट 'कॉकरोच इज बैक' नाम से बना दिया। इसके बायो में लिखा गया, 'कॉकरोच डोंट डाय', यानी कॉकरोच मरते नहीं।

इसके बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर और ज्यादा चर्चा शुरू हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रेंड का असर केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। पार्टी के कुल फॉलोअर्स में 96.06 प्रतिशत भारत से हैं, जबकि 0.66 प्रतिशत यूएई, 0.41 प्रतिशत अमरीका और 2.84 प्रतिशत अन्य देशों से जुड़े हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं।

युवाओं की बनी पहली पसंद

आंकड़ों के मुताबिक, सीजेपी के फॉलोअर्स में 76.21 प्रतिशत पुरुष और 23.79 प्रतिशत महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा 87.52 प्रतिशत यूजर्स की उम्र 18 से 34 वर्ष के बीच है। वहीं, 91.9 प्रतिशत ऑथेंटिसिटी रेट और 83.65 प्रतिशत रीचेबल यूजर यह दिखाते हैं कि यह ट्रेंड युवाओं के बीच कितनी तेजी से फैल रहा है। सोशल मीडिया पर कॉकरोच का यह क्रेज जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से साइबर ठग भी इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस की सलाह साफ है कि 'कॉकरोच' के पीछे इतने भी दीवाने मत बनो कि एक क्लिक आपकी जेब पर भारी पड़ जाए।

वंदे गंगा अभियान राजस्थान सरकार ने मंत्रियों और बोर्ड अध्यक्षों को सौंपी जिम्मेदारी

जयपुर। राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की मॉनिटरिंग के लिए मंत्रियों और विभिन्न बोर्ड व आयोग अध्यक्षों के जिलावार जिम्मेदारी तय की है। प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में दौरा कर अभियान पर नजर रखेंगे और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करेंगे। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अभियान अवधि में प्रभारी मंत्री कम से कम दो बार अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे। जिन जिलों में 25 मई को प्रभारी मंत्री या आयोग-बोर्ड अध्यक्ष का दौरा नहीं है, वहां कलक्टर प्रभारी सचिव एवं जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर अभियान शुरू कराएंगे।

बता दें कि प्रदेश में वर्षा की अनियमितता और लगातार बढ़ती जल आवश्यकताओं को देखते हुए परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण को अभियान का मुख्य आधार बनाया गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री 25 मई को टोंक में बीसलपुर बांध पर जल पूजन और शिव मंदिर में अभिषेक के साथ अभियान का शुभारंभ करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ईसरदा, बंध बरेठा और गालवा बांध का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। इसी दिन मुख्यमंत्री भरतपुर के गंगा माता मंदिर में आरती और सुजानगंगा नहर में दीपदान भी करेंगे।

राहुल गांधी पर भड़के केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, कहा- देश से माफी मांगे

हैलो सरकार न्यूज

भीलवाड़ा। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने भीलवाड़ा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग किया है, उसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी होगी, अन्यथा जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। मेघवाल रविवार को ग्रोथ सेंटर में भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन की एजीएम में शामिल होने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे।

इस दौरान राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के पुराने बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि राजनीति में विचारधारा अलग हो सकती है, विरोध हो सकता है, लेकिन नेताओं को शत्रु जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश के

जिम्मेदार पद पर हैं, इसलिए उन्हें अपनी भाषा और आचरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी की देशभर में चल रही चर्चा पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सोशल मीडिया की देन है। उन्होंने कहा कि जब यह राजनीतिक पार्टी बनेगी तब उस पर चर्चा की जाएगी, फिलहाल इस विषय पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल के क्रियान्वयन में हो रही देरी को लेकर मेघवाल ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में संसद से पारित इस कानून को लागू करने के लिए सरकार जरूरी संशोधन करना चाहती थी, लेकिन अंतिम समय में टीएमसी, सपा और द्रमुक जैसे दलों ने अपना रुख बदल लिया।

महिला आरक्षण कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा

उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी सभी दलों के बीच सहमति बनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है। महिलाओं को अधिकार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मेघवाल ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र और मजबूत होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी दलों के सहयोग से महिला आरक्षण कानून को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा।

सरकारी वाहन से शराब ले जाने का वीडियो वायरल, जांच की मांग

जोधपुर। शहर के झालामंड क्षेत्र स्थित मोती मार्केट ब्रिज के पास एक कथित सरकारी वाहन में दिनदहाड़े शराब की पेटियां ले जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को एक जागरूक नागरिक द्वारा रिकॉर्ड कर साझा किया गया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक वाहन, जिसे स्थानीय लोग सरकारी बता रहे हैं, शराब के ठेके पर रुकता है। बताया जा रहा है कि वाहन चालक पहले फोन पर ठेकेदार से बातचीत करता है, जिसके बाद दुकान का सेल्समैन बाहर आकर वाहन में शराब की पेटी रखता है। घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर यह कि संबंधित वाहन किस विभाग का है और क्या सरकारी वाहन का इस तरह निजी उपयोग किया जा रहा था। साथ ही यह भी चर्चा का विषय है कि रविवार के दिन, जब अधिकांश सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं, तब इस तरह की गतिविधि क्यों हो रही थी।

स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रशासन और संबंधित विभागों से अपेक्षा की जा रही है कि वे वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।

फिलहाल, प्रशासन की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में महत्वपूर्ण बदलाव, अब तकनीकी अपग्रेडेशन पर मिलेगा एक करोड़ रुपये तक का अनुदान

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। मुख्यमंत्रीभजनलाल शर्मा द्वारा की गई घोषणा के अनुपालना में राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब इस नीति के तहत तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2026-27 के तहत वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की थी।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि तकनीकी अपग्रेडेशन पर दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि से प्रदेश के उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक तकनीक को अपना सकेंगे। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ने

के साथ-साथ गुणवत्ता में भी सुधार होगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 दिसंबर, 2024 को राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति का अनावरण किया था और विभाग द्वारा 8 दिसंबर, 2024 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। अब निर्यातक उद्यमियों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए तकनीकी अपग्रेडेशन अनुदान राशि को बढ़ाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान

राज्य के उद्यमियों को निर्यातक बनाने के उद्देश्य से लागू की इस नीति के तहत निर्यातकों के दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपये और तकनीकी अपग्रेडेशन पर एक करोड़ रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 2 लाख रुपये तक का पुनर्भरण किया जाता है।

फिट इंडिया साइकिल संडे-मुख्य सचिव ने 5 KM साइकिल चला कर दिया खेलों के प्रति जागरूकता और फिटनेस का संदेश

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में रविवार को फिट इंडिया साइकिल संडे कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष इस आयोजन की थीम कॉमनवेल्थ डे 2030 रखी गई थी, जिसमें खिलाड़ियों, अधिकारियों, युवाओं और फिटनेस प्रेमियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण स्टेडियम परिसर के चारों ओर आयोजित साइकिल रैली रही।

इस रैली का उद्देश्य नागरिकों में शारीरिक स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवनशैली और कॉमनवेल्थ खेल 2030 के प्रति जागरूकता फैलाना था। इसके साथ ही जुम्बा सत्र भी आयोजित किया गया, जिसने कार्यक्रम को और अधिक ऊर्जावान बना दिया। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित हस्तियाँ उपस्थित रहीं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सीआरपीएफ जवानों एवं अन्य प्रतिभागियों के साथ 5 किलोमीटर

साइकिल चलाकर देशभक्ति और खेल उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल उत्सव नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य चेतना और कॉमनवेल्थ 2030 की तैयारी की दिशा में एक सार्थक शुरुआत है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें सीआरपीएफ के डीआईजी श्री बृजेश तथा सीआईएसएफ के सहायक कमांडेंट प्रमुख रहे।

राजस्थान राज्य खेल परिषद के सचिव प्रवीण गुप्ता और वित्त सचिव टीना सोनी ने भी साइकिलिंग कार्यक्रम में स्वयं भाग लेकर युवाओं को प्रेरित किया। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के अधिकारियों ने भी युवा भागीदारी और फिटनेस जागरूकता को प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व, सामुदायिक खेल भागीदारी और भारत के बढ़ते खेल परिवेश पर प्रकाश डाला। प्रतिभागियों ने इस पहल की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि जयपुर तथा पूरे राजस्थान में ऐसे और अधिक सार्वजनिक फिटनेस कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

कार्यक्रम का समापन एक सामूहिक संकल्प के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने फिटनेस, अनुशासन और वैश्विक मंच पर भारत की खेल महत्वाकांक्षाओं के समर्थन का प्रण लिया।

राजस्थान पुलिस का 'संडेज ऑन साइकिल' महाअभियान संपन्न, 18 हजार से अधिक लोग फिटनेस संकल्प से जुड़े

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। राजस्थान पुलिस के नेतृत्व में रविवार को प्रदेशभर में संडेज ऑन साइकिल अभियान का एक विशेष और भव्य संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जगाने के उद्देश्य से आयोजित इस राज्यव्यापी कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, जवानों और आम जनता सहित रिकॉर्ड 18,000 से अधिक प्रतिभागियों ने अत्यंत उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस महाअभियान का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक तक फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का प्रभावी संदेश पहुंचाना है, जो कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक %फिट इंडिया मूवमेंट% का एक अभिन्न हिस्सा है. डीजीपी के निर्देशन और खेल मंत्रालय के निर्देशों के तहत 75वां संस्करण

यह विशेष आयोजन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के तहत राष्ट्रमंडल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की खेल संस्कृति को मजबूत करना है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में इस वर्ष इस अभियान के 75वें संस्करण का सफल संचालन किया गया।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियन एवं मुख्य खेल अधिकारी रुपिंदर सिंघ के नेतृत्व में इस राज्यव्यापी अभियान को सुचारू रूप से अमलीजामा पहनाने के लिए उप महानिरीक्षक पुलिस, आर्म्ड बटालियन-द्वितीय विनीत कुमार बंसल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था।

18000 पुलिसकर्मियों और सामाजिक संगठनों का अनूठा संगम

रविवार की सुबह को पूरी तरह सेहत और नई ऊर्जा के नाम करते

हुए राज्य की समस्त जिला पुलिस, आरएसी बटालियनों, प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य पुलिस इकाइयों के लगभग 18,000 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया। इसके साथ ही स्थानीय साइकिलिंग क्लबों, स्वयंसेवी संस्थाओं, विभिन्न फिटनेस समूहों और सीएलजी सदस्यों सहित विशिष्ट व गणमान्य नागरिकों ने भी अपनी सशक्त भागीदारी निभाई। इस अभियान को लेकर माननीय प्रधानमंत्री ने भी पूर्व में अपने मन की बात कार्यक्रम के 117वें एपिसोड में इस पहल को विशेष रूप से सराहा था।

योग, जुम्बा, रन और साइकिलिंग से गूंजा पूरा राजस्थान

तनावमुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए आज सुबह ठीक 6:00 बजे राजस्थान पुलिस अकादमी और विभिन्न पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स सहित सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संडे की इस ऊर्जावान सुबह में सबसे पहले सामूहिक योग और ध्यान का सत्र आयोजित हुआ। इसके बाद जवानों और आमजन का उत्साह बढ़ाने के लिए जुम्बा डांस, रनिंग और रोप स्किपिंग जैसी शारीरिक फिटनेस गतिविधियाँ की गईं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में भव्य साइकिलिंग रैलियों का आयोजन किया गया, जिसने पूरे प्रदेश को फिटनेस के एक रंग में रंग दिया.

सोशल मीडिया पर छाया राजस्थान पुलिस का यह फिट अंदाज

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को काम के भारी दबाव और मानसिक तनाव से मुक्त करना भी है। राज्यभर से प्राप्त इस महाअभियान की अत्यंत आकर्षक व प्रेरक तस्वीरों और वीडियो को राजस्थान पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रमुखता से साझा किया जा रहा है, ताकि डिजिटल माध्यमों से भी स्वस्थ जीवनशैली और नियमित व्यायाम का यह सकारात्मक संदेश देश-दुनिया के कोने-कोने तक पहुंच सके।

युवा शक्ति, रेलवे और विकसित भारत का नया संकल्प

(लेखक--विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला)

किसी गरीब परिवार का युवा जब रेलवे,डाक विभाग,बैंकिंग,सुरक्षा बल या प्रशासनिक सेवा में चयनित होता है,तो वह केवल अपनी जिंदगी नहीं बदलता,बल्कि अपने पूरे परिवार को आर्थिक असुरक्षा से बाहर निकालता है। इसीलिए रोजगार मेलों के दृश्य भावनात्मक महत्व भी रखते हैं।

51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण में झलका आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास

भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में कुछ क्षण ऐसे होते हैं,जो केवल सरकारी आयोजनों तक सीमित नहीं रहते,बल्कि वे बदलते हुए राष्ट्र-चरित्र,व्यवस्था और समय की दिशा के प्रतीक बन जाते हैं। बीते दिनों ऐसा ही एक दृश्य तब सामने आया,जब देशभर के 51 हजार से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।यह कार्यक्रम केवल सरकारी नौकरियों के वितरण का औपचारिक आयोजन नहीं था,बल्कि उस नए भारत का प्रतिबिंब था,जो अपनी युवा शक्ति को विकास,आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ऊर्जा मानकर आगे बढ़ रहा है।विशेष महत्व की बात यह रही कि इन नियुक्तियों में 50 प्रतिशत से अधिक अवसर भारतीय रेल से जुड़े विभिन्न विभागों में प्रदान किए गए। यह तथ्य केवल भर्ती का सरकारी आंकड़ा नहीं,बल्कि आने वाले भारत की विकास दिशा का स्पष्ट संकेत भी है।यह बताता है कि केंद्र सरकार देश की आधारभूत संरचना,विशेषकर रेलवे नेटवर्क को 21वीं सदी के भारत की आर्थिक धुरी बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है।इस अवसर पर नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज का भारत युवाओं को अवसर देने वाला भारत है।सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं,बल्कि उन्हें धरातल तक पहुंचाकर युवाओं के हाथों में अवसर,विश्वास और आत्मसम्मान सौंपना है।उन्होंने यह भी कहा कि बीते वर्षों में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी,तकनीक आधारित और समयबद्ध बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए गए हैं, ताकि युवाओं को वर्षों तक प्रतीक्षा और अनिश्चितता के दौर से न गुजरना पड़े।दरअसल,पिछले कुछ वर्षों में 'रोजगार मेला' केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि शासन व्यवस्था की नई कार्यशैली के रूप में उभरा है। एक समय था,जब सरकारी भर्तियाँ वर्षों तक विवादों,लंबित परीक्षाओं, भ्रष्टाचार और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपों के बीच उलझी रहती थीं।लाखों युवा आयु सीमा पार होने की चिंता में अपने सपनों को टूटते हुए देखते थे। लेकिन अब मिशन मोड में रिक्त पदों को भरने और भर्ती प्रक्रियाओं को गति देने का प्रयास दिखाई देता है।यही कारण है कि देश के विभिन्न राज्यों और शहरों में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं।भारत जैसे विशाल और युवा देश में रोजगार का प्रश्न केवल आर्थिक विषय नहीं है।यह सामाजिक स्थिरता,पारिवारिक सुरक्षा,आत्मसम्मान और राष्ट्रीय आत्मविश्वास से भी गहराई से जुड़ा हुआ विषय है।जब किसी युवा के हाथ में नियुक्ति पत्र आता है,तब केवल एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती,बल्कि एक परिवार के सपनों को स्थिरता और समाज को नई ऊर्जा मिलती है।किसी गरीब किसान का बेटा,किसी मजदूर की बेटी या किसी निम्न मध्यमवर्गीय परिवार का युवा जब सरकारी सेवा में चयनित होता है,तब उसके साथ पूरा परिवार नई आशा से भर उठता है।ग्रामीण भारत में आज भी सरकारी नौकरी केवल रोजगार नहीं,बल्कि सम्मान,सुरक्षा और स्थायित्व का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है।गाँवों और कस्बों में सरकारी नौकरी पाने वाला युवा केवल अपने घर का भविष्य नहीं बदलता,बल्कि वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है।यही कारण है कि रोजगार मेलों के मंच केवल प्रशासनिक मंच नहीं रह जाते,बल्कि वे सामाजिक परिवर्तन और नई संभावनाओं के मंच बन जाते हैं।सरकारी सेवा को राष्ट्र सेवा का माध्यम बताते हुए युवाओं से ईमानदारी,संवेदनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया।यह बात भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना को भी व्यक्त करती है।कोई भी व्यवस्था तभी मजबूत होती है,जब उसमें कार्य करने वाले लोग सेवा भाव के साथ जनता के बीच काम करें।लोकतंत्र केवल संसद और सरकार से नहीं चलता,बल्कि उन लाखों कर्मचारियों और अधिकारियों से चलता है,जो रोज़मर्रा की व्यवस्था को आम जनता तक पहुंचाते हैं।आज भारत जिस 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, उसमें युवा शक्ति की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी युवा है।यह केवल जनसांख्यिकीय तथ्य नहीं,बल्कि विश्व राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की सबसे बड़ी ताकत है।दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वृद्ध होती आबादी की चुनौती से जूझ रही हैं, जबकि भारत के पास युवा ऊर्जा का विशाल आधार मौजूद है।यदि यही युवा शक्ति शिक्षित,प्रशिक्षित और रोजगारयुक्त होगी,तो भारत आने वाले दशकों में विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में शामिल हो सकता है।इस रोजगार मेले की सबसे बड़ी विशेषता भारतीय रेल में बड़ी संख्या में नियुक्तियाँ रही हैं।कुल नियुक्तियों में लगभग आधे से अधिक अवसर रेलवे से जुड़े विभिन्न विभागों में दिए गए।इसका महत्व केवल रोजगार तक सीमित नहीं है,बल्कि यह भारत की बदलती आर्थिक संरचना और विकास मॉडल को भी दर्शाता है।

भारतीय रेल केवल एक परिवहन तंत्र नहीं,बल्कि भारत की जीवन रेखा है।यह देश की आर्थिक गतिविधियों,सामाजिक एकता और सांस्कृतिक संवाद का सबसे बड़ा माध्यम है।हिमालय की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्री तट तक और पूर्वोत्तर के दुर्गम इलाकों से लेकर पश्चिमी भारत के औद्योगिक नगरों तक रेलवे भारत को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य करती है।आज जब भारत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास मॉडल की ओर बढ़ रहा है,तब रेलवे की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है।वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, अमृत भारत स्टेशन योजना, समर्पित माल गलियारे,हाईस्पीड रेल परियोजनाएं, रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम जैसी परियोजनाएं भारतीय रेल को नए युग में पहुंचा रही हैं।इन परियोजनाओं के लिए विशाल मानव संसाधन की आवश्यकता स्वाभाविक है।इंजीनियर, तकनीशियन,परिचालन कर्मचारी, सुरक्षा बल, प्रशासनिक अधिकारी और सेवा क्षेत्र से जुड़े हजारों पद रेलवे की नई संरचना का हिस्सा बन रहे हैं।यही कारण है कि रेलवे आज देश का सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता विभाग बनकर उभर रहा है।पिछले कुछ वर्षों में रेलवे को केवल यात्रा का माध्यम नहीं,बल्कि आर्थिक क्रांति का इंजन बनाने की दिशा में कार्य हुआ है।आज छोटे शहरों के रेलवे स्टेशन भी आधुनिक स्वरूप में विकसित किए जा रहे हैं। स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं स्थानीय व्यापार,पर्यटन और निवेश की नई संभावनाएं पैदा कर रही हैं।रेलवे के आधुनिकीकरण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार तेजी से बढ़ रहे हैं।एक समय था जब सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठते थे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली,वर्षों तक लंबित परिणाम,पेपर लीक और भर्ती घोटाले युवाओं में गहरी निराशा पैदा करते थे।पिछले कुछ वर्षों में तकनीक आधारित भर्ती प्रणाली ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया है।ऑनलाइन आवेदन,कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं,डिजिटल दस्तावेज सत्यापन और समयबद्ध चयन प्रक्रिया ने पारदर्शिता को मजबूत किया है।हालाँकि चुनौतियां अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं,लेकिन यह स्वीकार करना होगा कि तकनीकी सुधारों ने युवाओं के भीतर व्यवस्था के प्रति विश्वास को मजबूत किया है।आज का युवा केवल नौकरी नहीं चाहता,बल्कि वह सम्मानजनक और पारदर्शी अवसर चाहता है।यही कारण है कि जब नियुक्ति पत्र सीधे देश के सर्वोच्च नेतृत्व के माध्यम से युवाओं तक पहुंचता है,तो वह प्रशासनिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर मनोवैज्ञानिक विश्वास का भी निर्माण करता है।भारत की राजनीति में बेरोजगारी लंबे समय से बड़ा मुद्दा रही है। विपक्ष लगातार सरकार से रोजगार के आंकड़े मांगता रहा है,जबकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर,स्टार्टअप और स्वरोजगार आधारित अवसरों को रोजगार वृद्धि का आधार बताती रही है।ऐसे समय में रोजगार मेलों का आयोजन केवल प्रशासनिक पहल नहीं,बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि रिक्त पदों को भरने और युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सक्रियता दिखाई दे रही है।हालाँकि यह भी सच है कि भारत जैसे विशाल देश में केवल सरकारी नौकरियों के माध्यम से सभी युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।इसके लिए निजी क्षेत्र,उद्योग,कृषि आधारित उद्यम,पर्यटन,डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप संस्कृति को भी समान गति से आगे बढ़ाना होगा। 'स्किल इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया','मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी योजनाएं इसी व्यापक सोच का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य युवाओं को बहुआयामी अवसर उपलब्ध कराना है।आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है।डिजिटल तकनीक और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था ने लाखों नए अवसर पैदा किए हैं।इसके साथ-साथ सरकारी रोजगार की सामाजिक विश्वसनीयता आज भी बनी हुई है।यही कारण है कि रोजगार मेलों को लेकर युवाओं में विशेष उत्साह दिखाई देता है।

यदि आज भारत के विकास मॉडल को समझना हो,तो रेलवे को समझना आवश्यक है। रेलवे अब केवल ट्रेनों की आवाजाही तक सीमित नहीं रह गई है।यह देश की आर्थिक संरचना,लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और औद्योगिक विकास की रीढ़ बन चुकी है।समर्पित माल गलियारों के निर्माण से माल परिवहन की गति बढ़ रही है।इससे उद्योगों को लाभ मिलेगा और लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास छोटे शहरों को आधुनिक शहरी केंद्रों में बदलने की क्षमता रखता है।वंदे भारत ट्रेनें केवल आधुनिक ट्रेनों का प्रतीक नहीं,बल्कि उस आत्म विश्वासी भारत का प्रतीक हैं,जो अब तकनीक और गति दोनों में वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। रेलवे में बढ़ती नियुक्तियां इसी व्यापक परिवर्तन का हिस्सा हैं।आने वाले वर्षों में रेलवे,मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क के विस्तार से लाखों नए रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है।विश्व की अनेक बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वृद्ध होती आबादी की चुनौती से जूझ रही हैं।वहीं भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी मौजूद है।यह भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी।यदि युवाओं को शिक्षा,कौशल और रोजगार मिलेगा,तो भारत आने वाले दशकों में विश्व की अग्रणी आर्थिक शक्ति बन सकता है।यदि यही युवा अवसरों से वंचित रह गए,तो सामाजिक असंतोष और आर्थिक असंतुलन की स्थिति भी पैदा हो सकती है।इसी सोच के साथ युवाओं को ‘अमृत पीढ़ी’ बताते हुए विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब आज का युवा आत्मनिर्भर, प्रशिक्षित और अवसरों से संपन्न होगा।रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को केवल नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे,बल्कि यह संदेश भी दिया जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण की यात्रा में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित है।आज भी भारत का बड़ा हिस्सा गांवों और छोटे शहरों में बसता है।

संपादकीय

रूबियो की भारत यात्रा

क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कोलकाता से अपने भारत दौरे की शुरुआत करने के बाद जिस तरह दिल्ली आकर सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मिले और उनसे लंबी बात की, उससे यह प्रतीति होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने को विशेष महत्व दे रहे हैं। आम तौर पर किसी देश का विदेश मंत्री पहले अपने समकक्ष से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री से भेंट करता है, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री के मामले में यह क्रम टूटता दिखा। उन्होंने प्रधानमंत्री से लंबी बातचीत करने के बाद उन्हें अमेरिका आने का निमंत्रण भी दिया, लेकिन इसकी महत्ता तभी है, जब दोनों देशों के संबंधों में सुधार की प्रक्रिया वास्तव में गति पकड़े। भारत केवल इतने से संतुष्ट नहीं हो सकता कि अमेरिका उसकी प्राथमिकता में है और वह उसे खास महत्व दे रहा है, क्योंकि उसकी मौजूदा नीतियां भारतीय हितों के अनुकूल सिद्ध नहीं हो रही हैं। एक तो भारत-अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते में देरी हो रही है और दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उस पाकिस्तान को जरूरत से ज्यादा भाव दे रहे हैं, जिसे अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने धोखेबाज करार दिया था। अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव भी भारत के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस टकराव के चलते ईरान ने जिस तरह होर्मुज समुद्री मार्ग बाधित कर रखा है, उससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों में भारत प्रमुख है। अमेरिका-ईरान टकराव के कारण जो विश्वव्यापी ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, उसके लिए अमेरिका ही अधिक जिम्मेदार है। यह स्वाभाविक है कि अमेरिकी विदेश मंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच वार्ता में पश्चिम एशिया संकट यानी ईरान का मुद्दा भी अवश्य चर्चा में आया होगा। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह इस पर जोर दे कि अमेरिका पश्चिम एशिया संकट प्राथमिकता के आधार पर सुलझाए। इसी तरह वह व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़े। यह ठीक है कि भारत रवाना होने के पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत को एक महान देश और साझेदार बताते हुए यह कहा कि उसके साथ कई क्षेत्रों में काम करना है, लेकिन अभी तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बार भारत यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपनी यात्रा का उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मिलकर काम करना बताया। देखना है कि उनकी यह यात्रा इन उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक बन पाती है या नहीं? निःसंदेह देखना यह भी होगा कि अमेरिका चार देशों के संगठन क्वाड को लेकर कितनी गंभीरता का परिचय देता है?

दुनिया दीवानी फुटबॉल की, अब हमारी बारी!

(लेखक- दिलीप कुमार पाठक)

(25 मई विश्व फुटबॉल दिवस)

फुटबॉल दुनिया का ऐसा खेल है, जिसे समझने के लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं है, फुटबाल किसी भी भाषा में आए समझ आता है। मैदान पर पैर की एक जादुई ड्रिबल, एक सटीक पास और नेट से टकराती गेंद - यह वह रोमांच है जो दुनिया के हर कोने को एक धागे में पिरो देता है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने 25 मई को आधिकारिक तौर पर विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है। यह फैसला सिर्फ इस खेल की लोकप्रियता का जश्न नहीं है, बल्कि इस बात का सम्मान है कि फुटबॉल दुनिया में शांति, एकजुटता और युवाओं को जोड़ने का सबसे खूबसूरत जरिया है। जब पूरी दुनिया इस खेल के रंग में रंगी है, तब भारत के लिए यह दिन एक नई ऊर्जा और बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ने का अवसर है।

अक्सर कहा जाता है कि भारत सिर्फ क्रिकेट का दीवाना है, लेकिन सच यह है कि हमारे देश में फुटबॉल को लेकर एक खामोश क्रांति आकार ले रही है। कोलकाता के मैदानों का पारंपरिक जोश हो, केरल की गलियों की दीवानगी हो या पूर्वोत्तर के पहाड़ों से निकलती नई प्रतिभाएं - फुटबॉल का जज्बा हमारी रगों में तेजी से दौड़ रहा है। इंडियन सुपर लीग की सफलता और जमीनी स्तर पर शुरू हुए नए फुटबॉल प्रोजेक्ट्स ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय युवाओं में इस खेल को लेकर गजब का आकर्षण है। अब समय आ गया है कि इस जुनून को एक सही दिशा देकर हम वैश्विक मंच पर अपनी बड़ी पहचान बनाएं। भारत इस क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता है और इसके लिए हमें एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सबसे बेहतरीन शुरुआत स्कूलों और स्थानीय स्तर पर फुटबॉल फॉर ऑल यानी सबके लिए फुटबॉल अभियान चलाकर की जा सकती है। यदि हर पंचायत और नगरीय निकाय में बच्चों के लिए एक अदद मैदान और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कर दी जाएं, तो देश को हुनर खोजने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे कॉर्पोरेट जगत के पास सीएसआर फंड के जरिए ग्रामीण इलाकों में छोटी-छोटी फुटबॉल अकादमियां खोलने का शानदार मौका है। जब सरकार, कॉर्पोरेट और समाज मिलकर काम करेंगे, तो भारत में प्रतिभाओं का एक ऐसा ताना-बाना तैयार होगा जो भविष्य में वैश्विक कप्तानों को जन्म देगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल भारत के लिए एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर बन सकता है। खेल एक ऐसा माध्यम है जो बिना किसी राजनीतिक तनाव के दो देशों के लोगों के दिलों को जोड़ देता है। जब भारतीय फुटबॉल टीम अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में तिरंगा लहराएगी, तो यह न केवल देश की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाएगा बल्कि दुनिया भर में भारत के युवाओं के कौशल का डंका बजाएगा। मैदान के इस जादू का सबसे बड़ा फायदा हमारे स्वास्थ्य और सामाजिक ताने-बाने को मिलता है। आज के डिजिटल युग में जब बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर बंधे हैं, फुटबॉल उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक बेहतरीन वरदान है। 90 मिनट तक मैदान पर लगातार दौड़ना और तुरंत रणनीतियां बनाना दिल को मजबूत करता है, स्टेमिना बढ़ाता है और मोटापे जैसी बीमारियों को कोसों दूर रखता है। सबसे खास बात यह है कि फुटबॉल बच्चों को अकेले नहीं, बल्कि टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना सिखाता है। मैदान पर सीखी गई अनुशासन और आपसी तालमेल की यह कला जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती है। 25 मई का यह ऐतिहासिक दिन हमें यह भरोसा दिलाता है कि भारत के पास गति भी है और प्रगति का संकल्प भी। हमारी नई पीढ़ी के पैरों में वो दम है जो दुनिया के किसी भी मैदान पर अपना लोहा मनवा सकती है। जरूरत बस इस बात की है कि हम उनके इस हौसले को सही संसाधन और सही मंच दें। अगर आज हम मिलकर एक सही और सकारात्मक शुरुआत करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर दुनिया भारत के खेल को सलाम करेगी।

(लेखक पत्रकार हैं)

चिंतन मनन

संतोष का मार्ग

एक ऋषि अपने शिष्य कपिल के साथ श्रावस्ती नरेश के पास गए। ऋषि से मिलकर नरेश प्रसन्न हुए और उनके आदर-सत्कार में लग गए। इधर कपिल एक सेविका के रूप पर मुग्ध हो गया। उस सेविका ने कपिल से विवाह करने से पहले महंगे कपड़े और गहने मांगे। कपिल यह सब देने में असमर्थ था। सेविका ने इसकी व्यवस्था का तरीका बताते हुए कहा कि जो श्रावस्ती नरेश का प्रातःकाल सर्वप्रथम अभिवादन करता है, उसे वे दो स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करते है। कपिल रात बीतने के पहले ही नरेश के शयनकक्ष में घुसने लगा मगर चोर समझकर द्वारपालों ने उसे पकड़ लिया। नरेश के सामने उसने सब बातें सच-सच कह दीं। उसके भोलेपन पर प्रसन्न हो नरेश ने उसकी मुंहमांगी चीज देने का वचन दिया।

कपिल ने एक दिन का समय मांगा। सोचने लगा, दो स्वर्ण मुद्राएं तो कम हैं, क्यों न सौ मांग लूं, पर वे भी कितने दिन चलेंगी। उसने पूरा राज्य ही मांग लिया। श्रावस्ती नरेश निःसंतान थे, उन्हें योग्य व्यक्ति की तलाश भी थी। उन्हें कपिल योग्य लगा। वह बोले- तुमने मेरा उद्धार कर दिया। मैं तृष्णा रूपी सर्पिणी के पाश से छूट गया। यह सुनकर कपिल का विवेक जाग्रत हो गया।

वह बोला- महाराज, आप जिस दलदल से निकलना चाहते हैं, उसी में मैं गिरना नहीं चाहता। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह ऋषि के पास गया और उनसे सब कुछ कह डाला। ऋषि बोले- कामनाओं का कहीं अंत नहीं होता, इसलिए जितना अपने परिश्रम और ईश्वर कृपा से मिल जाए, उसी में प्रसन्न व संतुष्ट रहना चाहिए।

विचार मंथन

अधिकारों का अहंकार लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा

(लेखक- सनत जैन)

भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा माना जाता है। 1950 में लागू हुए संविधान ने देश के नागरिकों को समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबधी अधिकारी के साथ ही न्याय की गारंटी दी है। संविधान निर्माताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में ऐसी त्रिस्तरीय व्यवस्था तैयार की, जिसका उद्देश्य शक्ति का संतुलन बनाए रखना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना था। लेकिन वर्तमान समय में यह प्रश्न गंभीरता से उठने लगा है कि क्या ये संस्थाएं अपने मूल दायित्वों का निर्वाह उसी निष्पक्षता और संवेदनशीलता से कर रही हैं, जिसकी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने की थी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है। जब नागरिक अपने मताधिकार से सरकार चुनते हैं, तो वे केवल सत्ता नहीं सौंपते, बल्कि अपने अधिकारों और भविष्य की रक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य को देते हैं। संविधान ने स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित किया कि कोई भी संस्था निरंकुश न हो। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन्हें लागू करेगी और न्यायपालिका इस बात की निगरानी करेगी कि संविधान और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन न हो। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह धारणा मजबूत होती दिखाई दे रही है कि सत्ता और अधिकार का केंद्रीकरण बढ़ रहा है। सरकारें कठोर कानून बना रही हैं, जांच एजेंसियां लंबे समय तक लोगों को जेलों में बंद रख रही हैं और अदालतों में न्याय मिलने में असामान्य देरी हो रही है। इससे नागरिकों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या न्याय केवल कागजों तक सीमित होकर रह गया है। भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है, 'जमानत नियम है और जेल अपवाद।' इसके बावजूद आज अनेक मामलों में आरोपी वर्षों तक विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों में बंद रहते हैं। कई बार मुकदमे शुरू तक नहीं हो पाते, जबकि आरोपी अपनी संभावित सजा से अधिक समय जेल में बिता देता है। यह स्थिति केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक संकट में धकेल देती है। चिंता की बात यह है कि कठोर कानूनों के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था जरूरी हैं, लेकिन इनके नाम पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं मानी जा सकती। जब कानून का प्रयोग समान रूप से न होकर चयनात्मक रूप से होता दिखाई देता है, तब नागरिकों का विश्वास कमजोर होने लगता है। आज समाज में यह धारणा भी गहराती जा रही है कि प्रभावशाली और पूंजी संपन्न वर्ग के लिए नियम अलग हैं, जबकि आम नागरिकों के लिए अलग। न्याय में समानता लोकतंत्र की आत्मा है। यदि अदालतों के फैसलों में विरोधाभास, देरी और पक्षपात का आरोप बढ़ने लगे, तो यह केवल न्यायपालिका ही नहीं, पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है। न्यायपालिका लोकतंत्र का अंतिम प्रहरी मानी जाती है। इसलिए उससे सबसे अधिक संवेदनशीलता, संयम और निष्पक्षता की अपेक्षा होती है। अदालतों की टिप्पणियां और फैसले समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे में यदि न्यायालयों से ऐसी टिप्पणियां आती हैं, जो आम नागरिकों की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, तो असंतोष स्वाभाविक है। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। लोकतंत्र में असहमति को राष्ट्रविरोध नहीं माना जा सकता। सरकार और नागरिकों के बीच वैचारिक मतभेद लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा हैं। यदि विरोध की हर आवाज को कठोर कानूनों के जरिए दबाने की कोशिश होगी, तो इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रभावित होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों आत्ममंथन करें। अधिकार का अर्थ निरंकुशता नहीं, बल्कि जिम्मेदारी होता है। संविधान ने किसी भी संस्था को सर्वोच्च नहीं बनाया, बल्कि सभी को जवाबदेह बनाया है। यदि अधिकारों के साथ विनम्रता और संवेदनशीलता समाप्त हो जाए, तो लोकतंत्र धीरे-धीरे केवल व्यवस्था बनकर रह जाता है, जनविश्वास नहीं। इतिहास गवाह है कि जब जनता का विश्वास टूटता है, तब असंतोष भीड़ में बदल जाता है और भीड़ किसी नियम या व्यवस्था को नहीं मानती। इसलिए समय रहते लोकतांत्रिक संस्थाओं को यह समझना होगा कि संविधान केवल सत्ता चलाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि नागरिकों के सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प है। यदि इस संकल्प की अनदेखी हुई, तो उसके दुष्परिणाम पूरे राष्ट्र को भुगतने पड़ सकते हैं।

आईटीआर फाइलिंग में एआई की एंट्री, जरा सी चूक भी बुला सकती है मुसीबत

-आयकर विभाग ने आईटीआर जांच के लिए एआई और ऑटोमैटिक डेटा मैचिंग सिस्टम शुरू किया

नई दिल्ली ।

आयकर विभाग ने आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ऑटोमैटिक डेटा मैचिंग सिस्टम को लागू कर दिया है। इसका सीधा मकसद हर आय और लेन-देन पर बारीकी से नजर रखना है। ऐसे में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ढ्ढक्रभरते समय की गई कोई भी छोटी चूक आपको टैक्स नोटिस का शिकार बना सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि एआईएस (एनुअल इंफारमेंशन स्टेटमेंट) को ध्यान से जांचना अब बेहद जरूरी है। इसमें आपकी सैलरी, बैंक ब्याज, निवेश, प्रॉपर्टी और टीडीएस की पूरी जानकारी होती है। इसे फॉर्म 16, फॉर्म 26एएस, बैंक स्टेटमेंट जैसे अपने अन्य दस्तावेजों से मिलाकर ही आईटीआर फाइल करें। एआईएस और आपके आईटीआर में थोड़ा भी अंतर पाए जाने पर विभाग तुरंत नोटिस भेज सकता है। सैलरी का गलत विवरण, बैंक ब्याज छिपाना या टीडीएस का गलत दावा आम गलतियां हैं। शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बिक्री से हुए कैपिटल गेन को सही दिखाना अनिवार्य है। कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न और आईटीआर आंकड़ों का मिलान महत्वपूर्ण है, एआई सिस्टम किसी भी विसंगति को तुरंत पकड़ेगा। इसलिए हर जानकारी सटीक व स्पष्ट दें

कपास आयात शुल्क हटाने पर सरकार गंभीर

कपड़ा उद्योग को मिल सकती है राहत

नई दिल्ली ।

कच्चे कपास के आयात पर लगने वाले 11 प्रतिशत सीमा शुल्क को हटाने की मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के बीच परामर्श अंतिम चरण में है, जिससे घरेलू कपड़ा उद्योग को बढ़ती लागत के बोझ से राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर गहन चर्चा कर रहे हैं। घरेलू कपड़ा उद्योग लंबे समय से आयात शुल्क हटाने की मांग कर रहा है ताकि कपास की बढ़ती कीमतों से उद्योग पर बढ़ रहे लागत के बोझ को कम किया जा सके। अधिकारी ने संकेत दिया कि परामर्श प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है और निकट भविष्य में इस पर अंतिम निर्णय होने की प्रबल संभावना है। हाल ही में परिधान उद्योग और निर्यातकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तथा कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर इस शुल्क को हटाने की जोरदार मांग उठाई थी। उद्योग के अनुसार चालू वर्ष में कपास की अनुमानित आवश्यकता लगभग 337 लाख गांठ (एक गांठ 170 किलोग्राम) है, जबकि 2025-26 सत्र में आवक केवल 292.15 लाख गांठ रहने का अनुमान है।

पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी, कुछ शहरों में गिरावट

महानगरों में स्थिरता ग्लोबल उतार-चढ़ाव के बीच चेन्नई में महंगा हुआ तेल

नई दिल्ली ।

सरकारी तेल कंपनियों ने रे विवार को पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। ग्लोबल मार्केट में जारी उतार-चढ़ाव और देश के टैक्स स्ट्रक्चर के बीच आम उपभोक्ताओं को मिला-जुला अनुभव मिला है। जहां दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कीमतें पूरी तरह स्थिर बनी हुई हैं, वहीं पटना, नोएडा और गुरुग्राम जैसे शहरों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दूसरी ओर चेन्नई में तेल थोड़ा महंगा हुआ है। देश के चार बड़े महानगरों दिल्ली में पेट्रोल 99.51 प्रति लीटर और डीजल 92.49 रुपए प्रति लीटर के पुराने भाव पर ही मिल रहा है। इसी तरह मुंबई में भी पेट्रोल 108.45 प्रति लीटर और डीजल 95.02 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है। राहत की बात यह है कि बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 53 पैसे सस्ता होकर 110.47 और डीजल 50 पैसे गिरकर 96.53 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है।

कतर की कंपनी ने अडाणी ग्रुप के 48.05 लाख शेयर बिड़ला म्यूचुअल फंड को बेचे

आज शेयर बाजारों में अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर पर रहेगा फोकस

नई दिल्ली।

कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से संबद्ध कतर होल्डिंग एलएलसी ने खुले बाजार में सौदे के जरिए अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के 48.05 लाख शेयर 643 करोड़ रुपए में बिड़ला म्यूचुअल फंड को बेच दिए हैं। एसई पर थोक सौदों के बारे में उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक कतर होल्डिंग एलएलसी ने शुक्रवार को 48,05,974 शेयरों को 1,339 रुपए प्रति शेयर के औसत भाव पर बेचा। यह कंपनी में 0.40 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है। इस दौरान बिड़ला म्यूचुअल फंड ने इतने ही शेयर उसी कीमत पर खरीद लिए। इस खबर के सामने आने के बाद अब सोमवार को शेयर बाजारों में अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर फोकस में रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने तिमाही नतीजों का ऐलान पिछले महीने किया था। कंपनी ने दी जानकारी में बताया था कि जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कुल नेट प्रॉफिट 723 करोड़ रुपए है। सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 1.3 फीसदी का इजाफा हुआ। एक साल पहले इसी मार्च तिमाही में अडाणी ग्रुप की इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 714 करोड़ रुपए रहा था। जनवरी से मार्च 2026 में कंपनी की इनकम 7588.08 करोड़ रुपए रही। एक साल पहले मार्च क्वार्टर के दौरान कंपनी की कुल कमाई 6596.39 करोड़ रुपए रहा। बता दें वित्त वर्ष 2026 में अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस का नेट प्रॉफिट 2392.75 करोड़ रहा था। यानी पिछले वित्त वर्ष की तुलना में दो गुना ज्यादा। तब कंपनी का नेट प्रॉफिट 921.69 करोड़ रुपए रहा था। शुक्रवार को अडाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर बीएसई में 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी के साथ 1368 रुपए के स्तर पर बंद हुए थे।

रेलवे को मिलेगी रफ्तार! आईआरएफसी जुटाएगी 2 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज

नई दिल्ली ।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) ने चालू वित्त वर्ष में रेलवे परियोजनाओं के विस्तार के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के जरिये 2 अरब डॉलर जुटाने की योजना बनाई है। यह धनराशि मुख्य रूप से जापानी येन में जुटाई जाएगी और कंपनी के 70,000 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाने के कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है। आईआरएफसी के एक प्रमुख अे धिकारी ने बताया कि कंपनी ने पहले ही बैंकों के एक समूह के साथ 1.1 अरब डॉलर के बराबर जापानी येन में ईसीबी ऋण जुटाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। परियोजनाओं की मजबूत पाइपलाइन को देखते हुए जून तिमाही के भीतर ही धनराशि का वितरण शुरू होने की उम्मीद है। यह ऋण पांच वर्ष की अवधि के लिए लिया गया है और इसका उपयोग रेलवे क्षेत्र से जुड़ी या ईसीबी दिशानिर्देशों के तहत अनुपालन वाली अन्य परियोजनाओं के वित्तपोषण में किया जाएगा। रेल मंत्रालय के तहत आने वाली नवरत्न कंपनी आईआरएफसी ने चालू वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृति और लगभग 40,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है।

निर्यात बढ़ाने को एफटीए का प्रभावी कार्यान्वयन जरूरी: विशेषज्ञ

भारत में उपयोग दर 25 फीसदी पर, अब हस्ताक्षर से ज्यादा लागू करने पर हो ध्यान

नई दिल्ली ।

विशेषज्ञों का मानना है कि मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के मोर्चे पर भारत की अगली प्राथमिकता उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन और निर्यातकों को इनका इस्तेमाल सिखाने की होनी चाहिए। कई बड़े एफटीए पर हस्ताक्षर के बावजूद, असली चुनौती उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार और उद्योग को अब एफटीए पर हस्ताक्षर से एफटीए के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वर्तमान में भारत में एफटीए की उपयोग दर लगभग 25 प्रतिशत है, जो विकसित देशों के 70-80 प्रतिशत से काफी कम है, जिससे भारतीय निर्यातक पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे। एक कंसल्टिंग फर्म ने कहा कि एफटीए के लाभ सीमा शुल्क स्तर पर इस्तेमाल हों और निर्यात बढ़ाएं। भारत ने अनेक महत्वपूर्ण बाजारों से करार किए हैं, जो वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव में नए व्यापारिक रास्ते खोल सकते हैं। विशेषज्ञों ने कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग, फार्मा जैसे क्षेत्रों को उत्पादन से जुड़ी (पीएलआई) जैसी योजनाओं का अतिरिक्त समर्थन तथा अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता व हरित नियमों (विशेषकर यूरोपीय बाजारों के लिए) के अनुरूप घरेलू प्रमाणन प्रणाली मजबूत करने का सुझाव दिया है।

सन फार्मा: गिरावट में खरीदारी का मौका? नई दवा और बुलंद टारगेट से चमकेगा शेयर

शेयर ने छुआ 52-वीक हाई, शुक्रवार को दिखी मुनाफावसूली

नई दिल्ली।

फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज के शेयरों ने हाल ही में अपने 52-वीक हाई को छुआ, लेकिन सप्ताह के अंत में हुई हल्की मुनाफावसूली ने निवेशकों के मन में सवाल खड़े कर दिए। हालांकि, बाजार विशेषज्ञ इसे खरीदारी के एक बेहतरीन अवसर के रूप में देख रहे हैं। कंपनी की नई डायबिटीज और मोटापे की दवा सेमाग्लूटाइड (जीएलपी-1) के सफल क्लीनिकल ट्रायल और ब्रोकरेज फर्म एचडीएफसी सिक्योरिटीज की बाय रेटिंग के साथ बढ़ाए गए टारगेट प्राइस ने निवेशकों के लिए सुनहरे भविष्य का संकेत दिया है। सन फार्मा के शेयर ने इस हफ्ते 1917.15 रुपये के 52-वीक हाई को छुआ, जो इसके ऑल-टाइम हाई से केवल 4 फीसदी नीचे है। शुक्रवार को 2.43 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 1,845.20 रुपये पर बंद होने के बावजूद, विश्लेषक इसे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु मान रहे हैं। कंपनी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इसकी नई दवा सेमाग्लूटाइड मानी जा रही है। यह दवा डायबिटीज और मोटापे के इलाज में वैश्विक स्तर पर काफी प्रभावी साबित हुई है। सन फार्मा द्वारा विकसित इसका ओरल सॉलिड फॉर्म (खाने वाली गोली) अपने क्लीनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है और अब भारतीय ड्रग रेगुलेटर से अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा है। यह दवा घरेलू बाजार में कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। चौथी तिमाही के शानदार नतीजों के

बाद, ब्रोकरेज हाउस एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने सन फार्मा पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,120 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। ब्रोकरेज के अनुसार, कंपनी के ग्रॉस मार्जिन में 118 बेसिस पॉइंट का प्रभावशाली सुधार देखा गया है। हालांकि कर्मचारियों की सैलरी और रिसर्च पर हुए खर्च के कारण ऐ बिटा ग्रोथ 3 फीसदी तक सीमित रही, लेकिन कंपनी का ग्लोबल स्पेशियलिटी बिजनेस 20त्न और भारतीय कारोबार 15त्न की दर से बढ़ा है। इलुम्या, सेक्रा और विनलेवी जैसे प्रमुख ब्रांड्स की मजबूत वैश्विक मांग अमेरिकी बाजार में संभावित सुस्ती के प्रभाव को बेअसर करने में सक्षम है। ऐसे में, विश्लेषकों का मानना है कि सन फार्मा लंबी अवधि के निवेशकों को बंपर रिटर्न देने की राह पर है।

सोना 3 लाख तो चांदी 5 लाख रुपए के जा सकती है पार, बढ़ी टेंशन

रॉबर्ट कियोसाकी ने गोल्ड-सिल्वर की कीमतों को लेकर की भविष्यवाणी

नई दिल्ली।

'रिच डैड पुअर डैड' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को लेकर भविष्यवाणी की है। साथ ही उन्होंने शेयर बाजार में आने वाले समय में भारी गिरावट की बात कही है, जिसकी वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म है। सोशल मीडिया पोस्ट में रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा- दिग्गज मार्केट विश्लेषक जिम रिकाड्र्स का मानना है कि गोल्ड का रेट 1000 डॉलर प्रति आउंस तक पहुंच सकता है। वहीं, चांदी का रेट 200 डॉलर प्रति आउंस तक पहुंच सकता है। इस समय सोने का रेट 4500 डॉलर प्रति आउंस है। वहीं, चांदी का रेट 75 डॉलर प्रति आउंस है यानी घरेलू बाजार में सोने का रेट 300000 रुपए और चांदी का रेट 500000 रुपए के पार जा सकता है। ईंधन की कीमतों में जारी तेजी की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई है, जिसका असर वहां के शेयर बाजारों पर भी दिख रहा है। वैश्विक अस्थिरता की वजह से शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय शेयर बाजार में इससे अछूता नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी अपने पोस्ट में लिखते हैं कि अच्छे निवेशक भविष्य को देख लेते हैं और उसी हिसाब से एक्शन लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की नई भविष्यवाणी की वजह से एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई है। इस बात की बहस छिड़ गई है कि क्या आने

वाले समय में एक बार फिर से दुनिया मंदी की ओर बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 158117 रुपए प्रति 10 ग्राम था। 23 कैरेट गोल्ड का रेट 157484 रुपए, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 144835 रुपए, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 118588 रुपए और 14 कैरेट गोल्ड का रेट 92498 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं, चांदी का रेट शुक्रवार की शाम को 266000 रुपए था। बता दें शनिवार और रविवार को छुट्टी की वजह से नई कीमतें जारी नहीं की गई हैं। बता दें पीएम मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है।

घरेलू पर्यटन पर ईजमाई ट्रिप की नई उड़ान, एआई और विरासत से मजबूत होगा सफर

90 फीसदी आय घरेलू यात्रा से, एआई और विरासत परियोजनाओं में निवेश से मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली ।

यात्रा बुकिंग मंच ईजमाई ट्रिप (ईएमटी) भारत में घरेलू पर्यटन के बढ़ते रुझान का लाभ उठाते हुए दीर्घकालिक वृद्धि और अपने यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर केंद्रित है। कंपनी के एक अे धिकारी ने बताया कि उनकी करीब 90 फीसदी आय घरेलू यात्रा से आती है और वे बदलते भारतीय यात्री अनुभवों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अे धिकारी ने कहा कि भारतीयों में घरेलू पर्यटन को लेकर जबरदस्त रुचि है। भारतीय यात्री अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहकर सांस्कृतिक, धार्मिक, अनुभव-आधारित और क्षेत्रीय पर्यटन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, विशेषकर देश के विभिन्न हिस्सों की विरासत और संस्कृति को देखने में। दीर्घकालिक संभावनाओं को देखते हुए ईजमाई ट्रिप अपनी सीएसआर इकाई ईजमाई ट्रिप फाउंडेशन के माध्यम से कुतुब मीनार परिसर में सेवी कैफेटेरिया जैसी पर्यटक-केंद्रित परियोजनाएं शुरू कर रही है। ऑनलाइन यात्रा क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच, कंपनी कृत्रिम मेधा (एआई) में भी निवेश कर रही है, ताकि सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके, ग्राहकों को व्यक्तिगत अनुभव मिल सकें और डिजिटल मंच मजबूत हो।

कोल इं डिया का सिनगैस उत्पादन पर जोर, ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती

गैस आपूर्ति में दिककतों के बीच कोल इंडिया की सिनगैस इकाइयां लगाने की योजना

नई दिल्ली ।

सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण गैस आपूर्ति में आ रही बाधाओं से निपटने और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोयले से सिनगैस उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की तैयारी में है। सिनगैस, मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग बिजली, उर्वरक और स्वच्छ ईंधन बनाने में होता है। कोल इंडिया, जो देश के कुल कोयला उत्पादन में 80 फीसदी से अधिक का योगदान करती है, इस दिशा में शुरुआती कदम उठा चुकी है। कंपनी इन संयंत्रों को या तो कोयला खदानों के पास (पिटहेड) या फिर औद्योगिक उपभोक्ताओं जैसे उर्वरक संयंत्रों, गैस आधारित बिजलीघरों और डायरेक्ट-रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) इकाइयों के समीप स्थापित करेगी।

यह पहल राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन और रासायनिक कच्चे माल की सुरक्षा को सुदृढ़ करने की सरकारी रणनीति का हिस्सा है। इन परियोजनाओं को बिल्ड-ओन-ऑपरेट या बिल्ड-ऑपरेट-मेंटेन मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसके लिए कंपनी ने संभावित बोलीदाताओं की

पहचान हेतु रुचि पत्र जारी किए हैं। इसके अलावा सीआईएल उन औद्योगिक ग्राहकों की भी तलाश कर रही है जो दीर्घकालिक समझौतों के तहत सिनगैस का उपयोग कर सकें।

इस कदम का उद्देश्य कोयले के परिवहन लागत को कम करना, उद्योगों को सस्ती और विश्वसनीय सिनगैस आपूर्ति सुनिश्चित करना, तथा स्वच्छ ईंधन, उर्वरक और रसायन उत्पादन के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हीरो मोटोकॉर्प का चालू वित्त वर्ष में दोहरे अंक की वृद्धि का लक्ष्य

12 से अधिक नए उत्पाद उतारेगी कंपनी

नई दिल्ली।

देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन विनिर्माता हीरो मोटोकॉर्प ने वित्तीय वर्ष 2026-27 तक दोहरे अंक की वृद्धि हासिल करने का भरोसा जताया है। कंपनी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 12 से अधिक नए उत्पाद बाजार में उतारेगी और इलेक्ट्रिक स्कूटर कारोबार को तेजी से बढ़ाएगी। कंपनी के एक अे धिकारी के अनुसार स्कूटर कारोबार, विशेषकर इलेक्ट्रिक सेगमेंट, भविष्य के विकास का प्रमुख केंद्र होगा। उन्होंने 2030 तक कुल स्कूटर बिक्री में इलेक्ट्रिक स्कूटर की 50 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा। उन्होंने कम प्रदूषण वाले पावरट्रेन की बढ़ती मांग के मद्देनजर बाजार में अग्रणी स्थिति बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा` कि भारतीय दोपहिया बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा मानी, लेकिन बताया कि पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने अपनी

बाजार स्थिति मजबूत की है। सियाम के आंकड़ों के अनुसार, हीरो ने अपनी अग्रणी बढ़त फिर से बढ़ाई है, जिसका श्रेय स्कूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, 125 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल और प्रवेश स्तर की बाइकों में मजबूत प्रदर्शन को जाता है। चालू वित्त वर्ष में भी दोहरे अंक की वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें निर्यात और इलेक्ट्रिक वाहनों की भूमिका अहम होगी।

वैश्विक कारकों और घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर निर्भर करेगी शेयर बाजार की चाल

दिग्गज कंपनियों के परिणामों पर भी रहेगी निवेशकों की नजर

मुंबई ।

घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रही गिरावट के बाद इस सप्ताह में निवेशकों की नजर प्रमुख वैश्विक कारकों और घरेलू उद्योग के आंकड़ों पर टिकी रहेगी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर हर दिन आ रहे अलग-अलग बयानों से बाजार में जारी अनिश्चितता और उतार-चढ़ाव प्रमुख कारक होंगे। पिछले सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों में काफी उठापटक देखने को मिली, जहां एक दिन बाजार में तेजी दर्ज हुई तो अगले ही दिन वह फिसलता दिखा। यह रुझान मुख्य रूप से अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर आ रहे परस्पर विरोधी बयानों के कारण रहा, जिसने निवेशकों के सेंटिमेंट को प्रभावित किया। इस सप्ताह में भी इन वैश्विक घटनाक्रमों पर बाजार की पैनी नजर रहेगी, क्योंकि भू-राजनीतिक खबरें बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। घरेलू मोर्चे पर अप्रैल माह के औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) के आंकड़े सप्ताह के दौरान जारी होने हैं। ये आंकड़े देश की आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक वृद्धि की तस्वीर पेश करेंगे, जिसका सीधा असर निवेश धारणा पर पड़ सकता है। यदि आंकड़े उम्मीद से बेहतर रहे तो बाजार को गति मिल सकती है, अन्यथा नकारात्मक प्रभाव भी संभव है। इसके अलावा कुछ दिग्गज कंपनियों, जैसे ओएनजीसी और इंडिगो, के वित्तीय परिणाम भी सामने आने वाले हैं। इन परिणामों से कंपनियों के प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं को लेकर तस्वीर साफ होगी, जो बाजार के सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकती है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा समय में बाजार का सेंटिमेंट धीरे-धीरे सुधर रहा है और निवेशक हर गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देख रहे हैं। हालांकि, उन्होंने ट्रेडर्स को सलाह दी है कि वे इस सप्ताह बेहद चुनिंदा शेयरों में ही हाथ डालें और जोखिम प्रबंधन का पूरा ध्यान रखें। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार पूरी तरह से वैश्विक खबरों और भू-राजनीतिक गतिविधियों के अनुसार चल रहा है।

बीते सप्ताह कमजोर रुपया और बढ़ती मांग से तेल-तिलहन बाजार में मजबूती

आयातकों का घाटा घटने से भी मिली कीमतों को मदद, भविष्य में रकबा बढ़ने के आसार

नई दिल्ली ।

बीते सप्ताह रुपये के मूल्य में गिरावट और देश में बढ़ती मांग के चलते बीते सप्ताह सभी तेल-तिलहनों के दाम मजबूत रहे। डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से आयातित खाद्य तेल महंगे हो गए, जबकि घरेलू मांग ने स्थानीय तिलहन बाजारों को भी सहारा दिया। बाजार सूत्रों के अनुसार डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट ने आयातित सोयाबीन तेल-तिलहन, कच्चा पामतेल (सीपीओ) और पामोलीन जैसे तेलों को महंगा कर दिया। आयातकों ने भी लागत से नीचे माल बेचने का घाटा कम किया, जिससे इनके भाव में मजबूती आई। घरेलू मोर्चे पर सूरजमुखी तेल में वैश्विक वृद्धि के बाद मूंगफली की मांग बढ़ने से इसके दाम सुधरे, हालांकि यह अभी भी एमएसपी से नीचे है। बिनौला तेल में भी सुधार दिखा, क्योंकि उत्तर भारत की बंद मिलों के चलते महाराष्ट्र से महंगी आपूर्ति करनी पड़ रही है। वहीं, शुरुआत में कम भाव रहने से सरसों की खपत और पेराई में तेजी आई, जिससे इसके तेल-तिलहन के भाव मजबूत हुए। अच्छे दाम मिलने से उत्साहित किसान भविष्य में सरसों, सोयाबीन और कपास की खेती का रकबा बढ़ा सकते हैं। यह कदम देश को तेल-तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में सहायक हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि बीते सप्ताह सरसों दाना 450 रुपये के सुधार के साथ 7,625-7,650 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों तेल 800 रुपये के सुधार के साथ 15,650 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल क्रमशः 115-115 रुपये के सुधार के साथ क्रमशः 2,575-2,675 रुपये और 2,575-2,720 रुपये टिन (15 किलो) पर मजबूत बंद हुए। समीक्षाधीन सप्ताह में सोयाबीन दाना और सोयाबीन लूज का थोक भाव क्रमशः 325-325 रुपये के सुधार के साथ क्रमशः 7,625-7,675 रुपये और 7,275-7,350 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। इसी प्रकार, दिल्ली में सोयाबीन तेल 75 रुपये सुधार के साथ 15,900 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन इंदौर तेल 125 रुपये के सुधार के साथ 15,850 रुपये और सोयाबीन डीगम तेल 35 रुपये सुधार के साथ 12,310 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ।

10 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में 19 आरोपियों को उम्रकैद, परिवार को मिला न्याय

नबरंगपुर (एजेंसी)। ओडिशा के नबरंगपुर जिले में 2016 के चर्चित तिहरे हत्याकांड और आगजनी मामले में कोर्ट ने 19 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला करीब 10 साल पुराना है, जिसने उस समय पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोपों को साबित मानते हुए सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उन्हें न्याय मिल गया। जानकारी के मुताबिक साल 2016 में गांव में हिंसक झड़प के दौरान तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद इलाके में आगजनी भी की थी ताकि सबूत नष्ट कर सकें। पुलिस जांच में सामने आया था कि पुरानी रंजिश और अंधविश्वास इस घटना की मुख्य वजह थे। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। पुलिस ने जांच में कई लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई लंबे समय तक चली, जिसमें अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने माना कि दोषियों ने सुनियोजित तरीके से अपराध को अंजाम दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त माना। फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील था। कोर्ट के फैसले को राज्य में कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से अहम माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि इतने सालों बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है।

गढ़चिरौली के जंगल में छिपी हथियार फैक्ट्री मिली, आठ माओवादी गिरफ्तार

गढ़चिरौली (एजेंसी)। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने जंगल में छिपाई माओवादियों की हथियार बनाने और स्टोर करने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यह कार्रवाई 'ऑपरेशन अंतिम प्रहार' के तहत की गई, जो सरेंडर कर चुके माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर की गई। सर्च ऑपरेशन में पुलिस को लेथ मशीन, पाइप, जनरेटर, बैटरी, ड्रिलिंग मशीन, सोलर पैनल और विस्फोटक सामग्री बनाने के उपकरण मिले। सुरक्षा बलों ने मौके पर ही सभी सामान को नष्ट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एके-47, इंसास, एसएलआर समेत 51 हथियार, भारी मात्रा में गोला-बारूद, डेटोनेटर और 65 लाख रुपए से ज्यादा नकदी बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद जिले में वांटेड माओवादियों की सूची लगभग खत्म हो गई है। गढ़चिरौली पुलिस और सीआरपीएफ ने इस अभियान में आठ माओवादियों को गिरफ्तार किया और पांच सीनियर कैडर ने सरेंडर किया। गिरफ्तार लोगों में कई बड़े माओवादी नेता शामिल हैं।

कोलकाता एयरपोर्ट मस्जिद शिफ्टिंग पर निर्णायक मंथन तेज

- 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद को हटाने या स्थानांतरित करने पर चर्चा जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में बदलते राजनीतिक माहौल के बीच कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनैशनल एयरपोर्ट परिसर में स्थित 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद को हटाने या स्थानांतरित करने का मामला फिर से गरमा गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी, जिला प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच लगातार हो रही बैठकों के बाद बकरीद के बाद इस पर कोई बड़ा और निर्णायक फैसला आने की संभावना है। यह घटनाक्रम सिर्फ एक धार्मिक स्थल या हवाईअड्डे के विस्तार का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसे बंगाल की बदलती राजनीति का एक महत्वपूर्ण संकेत भी माना जा रहा है, जहां वर्षों से लंबित संवेदनशील मामलों को अब गति मिल रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह मस्जिद एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से लगभग 150 मीटर अंदर और सेकेंडरी रनवे से मात्र 165 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस निकटता के कारण सेकेंडरी रनवे का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, जो हवाईअड्डे की सुरक्षा और परिचालन क्षमता के लिए एक चुनौती है। भाजपा लंबे समय से सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को प्राथमिकता देती रही है और अब राज्य एवं केंद्र की सोच में तालमेल दिखने से ऐसे कई पुराने और विवादित प्रोजेक्ट्स को गति मिल सकती है।

तकनीकी खराबी के बाद प्रशिक्षण विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

अलीगढ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में रविवार सुबह एक बड़ा विमान हादसा टल गया, जब प्रशिक्षण उड़ान पर निकले एक विमान में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। स्थिति गंभीर होते देख पायलटों ने जलाली क्षेत्र के पास विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई। जानकारी के अनुसार धनीपुर एयरपोर्ट से पायनियर कंपनी का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर रवाना हुआ था। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद विमान में तकनीकी समस्या आ गई। सुबह करीब 11 बजे पायलटों ने सूझबूझ और सतर्कता दिखाते हुए विमान को सुरक्षित नीचे उतार लिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं।

बारामूला में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई, आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षाबलों ने आतंकियों के एक छिपे ठिकाने का पर्दाफाश किया है। इसी के साथ ही बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया है। यह कार्रवाई निलसर कांडी इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान की गई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बारामूला पुलिस, 52 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान सुरक्षाबलों को 14 राउंड ओजी-7वी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अमुनिशन तथा 09 राउंड पीजी-7पी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अमुनिशन बरामद हुए। सुरक्षा एजेंसियां बरामद सामग्री की जांच कर रही हैं।

कांग्रेस गांधीवादी मूल्यों के बजाय गालियों वाली पार्टी बन गई है: पूनावाला

-मुसलमान के साथ अन्याय वाले राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पार्टी के मुस्लिम नेताओं से बैठक में एक ऐसी बात कह दी, जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। उन्होंने मुस्लिम नेताओं को अपने समुदाय से जुड़े मुद्दों को मुखरता से उठाने और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में राहुल गांधी ने कहा, कि अगर किसी मुसलमान के साथ अन्याय होता है तो उन्हें केवल 'अल्पसंख्यक' समूह के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि विशेष रूप से एक 'मुसलमान' के रूप में अपनी आवाज उठानी चाहिए। इसी के साथ राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में इस बात पर भी जोर दिया कि अगर दलितों, ओबीसी या सामान्य वर्ग के सदस्यों पर हमले होते हैं तो उस विशिष्ट समुदाय की स्पष्ट रूप से पहचान करके इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने जिस तरह से मुसलमानों के संदर्भ अपनी बात रखी उस पर राजनीति गरमा गई। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला।

पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी के इस कमेंट से कांग्रेस और उनके नेता के माइंडसेट का पता चलता है। इससे ये भी साफ होता है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। बीजेपी नेता ने कहा कि हिंदू को दो गाली, मुस्लिम की लो ताली, ये है वोट बैंक की कांग्रेस की प्रणाली। उन्होंने अपनी बात रखते हुए केरल के नए सीएम सतीशन का भी जिक्र किया। बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने आगे कहा कि कांग्रेस गांधीवादी मूल्यों के बजाय गालियों वाली पार्टी बन गई है। राहुल गांधी ने हाल ही में पीएम मोदी को गद्दार कहा था, जिसके बाद उनके करीबी सहयोगी अजय राय ने कथित तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने दावा किया कि ऐसा एआई या अन्य कारणों से हुआ था। उनके पिछले रिकॉर्ड को देखें, तो वह गलत भाषा से भरा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ 150 से ज्यादा गलत टिप्पणियां की हैं, क्योंकि वह ओबीसी और गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।

भारत-ओमान सेना प्रशिक्षण से रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मिलेगी और मजबूती

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और ओमान ने ओमान के सुल्तान के सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए दो भारतीय मोबाइल प्रशिक्षण टीमों द्वारा आयोजित एक विशेष सैन्य प्रशिक्षण पहल के जरिए अपनी बढ़ती रणनीतिक रक्षा साझेदारी को मजबूत किया। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच आयोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नेतृत्व एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के अधिकारियों ने भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों के साथ मिलकर किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य परिचालन समन्वय और संयुक्त रसद तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करना था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एकीकृत रक्षा स्टाफ के मुख्यालय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा- भारत-ओमान रक्षा सहयोग को सुदृढ़ बनाना भारतीय रक्षा मुख्यालय और तीनों सेनाओं के अधिकारियों से युक्त दो भारतीय मोबाइल प्रशिक्षण दल ने ओमान के सुल्तान की सशस्त्र सेना के कर्मियों के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षण आयोजित किया। ओमान की शाही सेना, शाही नौसेना, शाही वायु सेना और रक्षा मंत्रालय के करीब 110 अधिकारियों ने परिचालन और संयुक्त रसद प्रशिक्षण में भाग लिया, जिससे अंतर-संचालनीयता और भारत-ओमान रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ किया। यह घटनाक्रम विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा 18 मई को ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बदर बिन हमद अल बुसैदी से हुई टेलीफोन पर बातचीत के कुछ दिनों बाद सामने आया है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया संकट से संबंधित हालिया घटनाक्रमों के साथ-साथ भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर बात की थी।

केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़: 11 घंटे का लंबा इंतजार और दर्शन सिर्फ डेढ़-दो सेकंड के

देहरादून (एजेंसी)। चारधाम यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम में इस समय रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ के कारण भक्तों को दर्शन के लिए 10 से 11 घंटे तक लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड और भीड़ के दबाव के बीच श्रद्धालुओं को गर्भगृह में केवल डेढ़ से दो सेकंड तक ही रुकने का अवसर मिल पा रहा है।

जानकारी अनुसार हर दिन करीब 25 हजार से 30 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने से प्रशासन और मंदिर समिति के सामने व्यवस्थाएं संभालना बड़ी चुनौती बन गया है। भीड़ के चलते गुप्तकाशी से सोनप्रयाग तक 27 किलोमीटर के रास्ते पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। श्रद्धालुओं को यह दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे तक का समय लग रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग और ट्रैफिक नियंत्रण व्यवस्था लागू की है, लेकिन यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ने से दबाव बना हुआ है।

दर्शन का समय बढ़ाकर 22 घंटे किया

श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति ने मंदिर में दर्शन का समय बढ़ाकर लगभग 22 घंटे कर दिया है। भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए टोकन व्यवस्था भी लागू की गई है, हालांकि कई बार यात्रियों की अनियंत्रित संख्या के कारण यह व्यवस्था प्रभावी साबित नहीं हो पा रही है।

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुझाव

श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर जाने से पहले उत्तराखंड पर्यटन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अवश्य ही करवाएं। जो यात्री लंबी पैदल यात्रा या भीड़ से बचना चाहते हैं, वे आईआरसीटीसी की हेलीयात्रा सेवा के माध्यम से हेलीकॉप्टर टिकट बुक कर सकते हैं। इसी के साथ ही श्रद्धालु विशेष पूजा या वीआईपी दर्शन सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं, जिससे लंबी कतारों से बचने में मदद मिल सकती है। मंदिर प्रशासन के अनुसार तड़के सुबह या दोपहर में कपाट बंद होने के बाद शाम के समय दर्शन के लिए अपेक्षाकृत कम भीड़ रहती है। ऐसे समय में श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा मिल सकती है।

देश में बीजेपी के उभरने की असली वजह कांग्रेस की कमजोरियां हैं: उदयनिधि

- कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, हमारे से उन्होंने धोखा किया

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर हमला बोला। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस ने सीएम सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को अपना समर्थन दिया। उदयनिधि ने पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा कि डीएमके को कांग्रेस पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके कार्यकर्ताओं की मेहनत और एमके स्टालिन के नेतृत्व की वजह से सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस नेताओं में बुनियादी अहसानमंदी और शिष्टाचार की कमी है।

उदयनिधि ने धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के पांच विधायकों की जीत डीएमके कार्यकर्ताओं की वजह से हुई। जनता ने उन्हें इसलिए वोट दिया क्योंकि वे एमके स्टालिन को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन आज कुछ पदों के लालच में वे हमें बिना बताए ही भाग गए। हमें कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तमिलनाडु की जनता बहुत जल्द उन्हें करारा जवाब देगी।

उन्होंने पूरे देश में बीजेपी के आगे बढ़ने के लिए भी कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। उदयनिधि ने कहा कि पहले मुझे लगता था कि देश में बीजेपी की जीत की वजह पीएम मोदी और शाह हैं। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि भारत में बीजेपी के उभरने की असली वजह कांग्रेस की कमजोरियां हैं। हमारे नेता एमके स्टालिन ने पिछले चुनावों में कांग्रेस को अपने कंधों पर उठाया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। यह बयान डीएमके और कांग्रेस के बीच लगातार बढ़ रही कड़वाहट दिखाता है। डीएमके बैठक में कुछ प्रस्ताव भी पास किए गए, जिनमें कांग्रेस को पीठ में छुरा घोंपने वाला और सहयोगियों की मेहनत पर पलने वाला जोंक बताया गया। इसके साथ ही, उदयनिधि ने अपनी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे नए और पहली बार वोट देने वाले युवाओं के बीच जाकर उन्हें राजनीति के प्रति जागरूक करें।

वहीं दूसरी ओर डीएमके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दावा किया है कि टीवीके सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। स्टालिन ने कहा कि उनके पास कुल 120 विधायकों का ही समर्थन है। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने एआईएडीएमके को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वे नाकाम रहे। उनकी हालत आज दीवार पर बैठी बिल्ली जैसी है। यह सरकार किसी भी दिन गिर जाएगी। एमके स्टालिन ने उन वामपंथी और अन्य क्षेत्रीय दलों की भी आलोचना की, जो पहले सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे लेकिन अब मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जैसे बच्चे कुछ ही दिनों में नए खिलौनों से ऊब जाते हैं, वैसे ही तमिलनाडु के लोग भी इस अभिनेता के शासन से ऊब जाएंगे। तब वे दोबारा हमारे पास वैसे ही लौटेंगे, जैसे बच्चे अपनी मां के पास लौटते हैं।

तमिलनाडु में 3246 बदमाश हिरासत में, 419 ड्रग तस्कर गिरफ्तार

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु पुलिस ने 3246 बदमाशों को हिरासत में लिया और 419 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पिछले तीन दिनों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान की गई। अभियान के दौरान पुलिस ने 15,349 लोगों की जांच की। इनमें 12,650 हिस्ट्रीशीटर और 2,699 गैर-हिस्ट्रीशीटर शामिल थे। इनमें 844 लोगों को कई कानूनी धाराओं के तहत ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया। तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ लेने के 48 घंटे के अंदर विजय ने चार बड़े फैसले लिए थे। इनमें तमिलनाडु के हर जिले में करीब 65 एंटी-ड्रग टास्क फोर्स बनाने का फैसला शामिल था। पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह अभियान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के निर्देश पर चलाया गया। तमिलनाडु सरकार के निर्देश पर पुलिस राज्य में शांति और लोगों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम कर रही है। पुलिस बदमाशी, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार पर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम विजय ने कैबिनेट में 8 दलित विधायकों को शामिल कर बनाया रिकॉर्ड

-यह तमिलनाडु की राजनीति में प्रतिनिधित्व पर आधारित नए युग की शुरुआत

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु में डीएमके को सत्ता से हटाकर टीवीके ने सबको हैरान कर दिया। थलपति विजय ने जब से सीएम पद की शपथ ली, तब से वह लगातार चर्चा में हैं। अब उनके कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो रही है। यह चर्चा है कैबिनेट में अनुसूचित जाति के मंत्रियों की संख्या को लेकर है। तमिलनाडु के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कैबिनेट है। यह बढ़ोतरी, विजय के कार्यकाल के पहले साल में उनके बढ़ते जनादेश को दर्शाती है। इसके साथ ही कैबिनेट में सबसे ज्यादा एससी मंत्रियों को शामिल करने का एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है।

थलपति विजय की कैबिनेट में अनुसूचित जाति के 8 विधायक शामिल हैं। विजय की कैबिनेट को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। सरकार के दृष्टिकोण से 23 नए मंत्रियों को शामिल करना, सामाजिक समावेश और संतुलित प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। जानकारों का मानना है कि तमिलनाडु की पिछली कैबिनेट की तुलना में यह एक बड़ा बदलाव है, खासकर जब अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की बात आती है। कैबिनेट का हालिया विस्तार जाति संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, सहयोगी दलों को जगह देने और युवा प्रतिभाओं को शामिल करने का एक बेहतरीन मेल है। सीएम विजय समेत 35 सदस्यों तक पहुंचने के साथ, मंत्रिपरिषद की संख्या में अब बढ़ोतरी हुई है।

विजय की कैबिनेट में शामिल 8 अनुसूचित जाति के विधायक हैं जिनमें एस कमाली, वी गांधीराज, पी मथन राजा, डी लोगेश तमिलसेल्वन, के थेन्नारासु, पी विश्वनाथन, ए राजमोहन, वन्नी अरसु इनमें अनुभवी विधायकों के साथ-साथ राजनीति में अपेक्षाकृत नए चेहरे भी शामिल हैं, और यह महत्वपूर्ण मंत्रालयों में एससी प्रतिनिधित्व के लिए एक अच्छा संकेत है। 22 मई को मंत्रियों को शामिल करने के बीच ए एम शाहजहां (आईयूएमएल) और वन्नी अरसु (वीसीके) ने चेन्नई के राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। पापनासम सीट से आने वाले शाहजहां को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सौंपा गया है। वे एक समाज सेवक और एक चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। वे लंबे समय से तंजावुर में शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

विजय कैबिनेट के गठन में कांग्रेस, आईयूएमएल और वीसीके नेताओं के अलावा एससी नेताओं का चयन, सहयोगी दलों और सामाजिक पहुंच के जरिए राजनीतिक एकीकरण का एक संकेत है। चार सहयोगी दलों की भागीदारी के साथ, सरकार एक व्यापक मोर्चा बनाने का प्रयास कर रही है। यह फेरबदल महज प्रशासनिक नहीं है। यह तमिलनाडु की राजनीति में प्रतिनिधित्व पर आधारित एक नए युग की ओर इशारा करता है। शासन-प्रशासन में एससी और हाशिए पर पड़े समुदायों को अब और ज्यादा प्रतिनिधित्व और पहचान मिलेगी।

बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम के गठन की कवायद तेज

-यूपी समेत कई राज्यों की टीम व अध्यक्षों को लेकर जल्द हो सकता है फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम के गठन की कवायद तेज हो गई है। संगठन से सीधे जुड़े पदों के लिए पार्टी के बड़े नेताओं और आरएसएस के नेताओं के बीच संवाद हो रहा है। संकेत मिले हैं कि केंद्रीय टीम के साथ उत्तर प्रदेश व अन्य कुछ राज्यों की टीम व कुछ प्रदेशों के अध्यक्षों को लेकर भी जल्द फैसला हो सकता है। अगले माह से पार्टी आने वाले चुनावों को लेकर तैयारी भी शुरू कर देगी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने इस साल 20 जनवरी को अपना कार्यभार संभाला था। तब से अब चार माह हो चुके हैं, लेकिन नए केंद्रीय पदाधिकारियों को लेकर इंतजार बना हुआ है। पांच राज्यों में विधानसभाओं चुनाव के चलते इसमें देरी हुई, लेकिन अब पार्टी जल्द इस काम को पूरा करना चाहती है, ताकि उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तेज किया जा सके। अभी उत्तर प्रदेश की टीम पर मुहर नहीं लगी है इसलिए वहां पर काफी उहापोह है।

प्रदेश बीजेपी की नई टीम का खाका लगभग तैयार हो चुका है। दिल्ली में इसे अंतिम रूप देने की कवायद चल रही है। माना जा रहा है कि जल्द इस पर फाइनल बैठक हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के दिल्ली से बाहर होने के चलते अंतिम मुहर नहीं लग सकी है। इसका ऐलान 25 मई के बाद हो सकता है। सबसे ज्यादा कशमकश क्षेत्रीय अध्यक्षों को लेकर है। तमाम दावेदार भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी करने वाले कुछ चेहरे प्रदेश टीम से बाहर हो सकते हैं। कुछ मौजूदा प्रदेश महामंत्रियों की भूमिका बदलना भी तय माना जा रहा है। बीजेपी के राज्य मुख्यालय पर इन दिनों सन्नाटा है। यूपी के भाजपाई दिल्ली की ओर टकटकी लगाए हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नई टीम के गठन की कवायद में जुटी है। कुछ पदाधिकारियों का टीम से बाहर होना तय माना जा रहा है। कुछ ऐसे चेहरे शामिल हैं जिन्हें या तो पार्टी चुनाव लड़ने का मन बना रही है या फिर वे खुद टिकट के लिए ताल ठोंक रहे हैं। नितिन नबीन ने कहा है कि पार्टी की यात्रा सत्ता प्राप्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा की है। पार्टी की यात्रा केवल एक राजनीतिक दल के विस्तार की कहानी नहीं है, यह राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना, सेवा, संघर्ष और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के संकल्प की ऐतिहासिक यात्रा है। बीजेपी की शक्ति हमारी राष्ट्रवादी विचारधार और समर्पित कार्यकर्ता है। शनिवार को अपने जन्मदिन के मौके पर पटना में आयोजित प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष नबीन ने कहा कि 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ से लेकर बीजेपी तक की यात्रा संघ और कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम है।

मेलोडी महज टॉफी नहीं बल्कि चीन के लिए रचा गया चक्रव्यूह

नई दिल्ली (एजेंसी)। दुनिया जब 'मेलोडी' (पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी) के मीम्स और सोशल मीडिया रील्स के शोर-शराबे में डूबी हुई थी, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक बड़ा कूटनीतिक खेल खेला जा चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिन्होंने चीन की घेराबंदी पूरी तरह सेट कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम से बीजिंग को बड़ा झटका लगा है, जिसकी शुरुआत कुछ समय पहले द ग्रेट इटली डिवोर्स से हुई थी। कुछ साल पहले इटली, चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने वाला एकमात्र जी-7 देश बना था। हालांकि, जॉर्जिया मेलोनी ने सत्ता में आते ही चीन के इस कर्ज के जाल को पहचान लिया और इटली को आधिकारिक तौर पर इससे बाहर निकाल लिया। चीन को ठेंगा दिखाने के बाद इटली को एशिया में एक मजबूत और भरोसेमंद आर्थिक साझेदार की तलाश थी, जो चीन की जगह ले सके। यहीं पर न्यू इंडिया की एंट्री हुई। मोदी और मेलोनी की शानदार केमिस्ट्री दरअसल दुनिया को एक सीधा संदेश है कि इटली अब अपनी पूरी एशियाई रणनीति को बीजिंग से हटाकर नई दिल्ली पर शिफ्ट कर रहा है।

वैश्विक व्यापार के नक्शे पर नजर डालें तो भारत के लिए इटली की भौगोलिक स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत जब अपना सामान, टेक्नोलॉजी और एनर्जी यूरोप के बाजारों में भेजना चाहता है, तो उसके लिए भूमध्य सागर ही सबसे मुख्य रास्ता है, जिसके केंद्र में इटली स्थित है। इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए इटली खुद को भारतीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित कर रहा है। इटली के बंदरगाहों को भारत के मैन्युफैक्चरिंग बूम से जोड़कर दोनों देशों ने आने वाले 50 सालों की आर्थिक सुरक्षा का इंतजाम कर लिया है, जो चीन की ट्रेड दादागीरी को सीधी चुनौती है।

इसके अलावा, दशकों से तैयार हथियार खरीदने वाले भारत के साथ मेलोनी सरकार ने एक नया और स्मार्ट गेम शुरू किया है। इटली अब पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत की जमीन पर ही एडवांस रडार सिस्टम और मैरीटाइम डिफेंस जैसे क्षेत्रों में डिफेंस इक्विपमेंट्स का सह-उत्पादन करेगा। सोशल मीडिया पर दिखने वाली क्यूट और मजेदार मेलोडी सेल्फी तो सिर्फ एक पैकेजिंग है। इसके पीछे की असली हकीकत यह है कि यूरोप में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए भारत को इटली की जरूरत है और चीन को आर्थिक व रणनीतिक टक्कर देने के लिए इटली को भारत का साथ चाहिए। दोनों देशों ने मिलकर ड्रैगन के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा है, उसने बीजिंग की रातों की नींद उड़ा दी है।

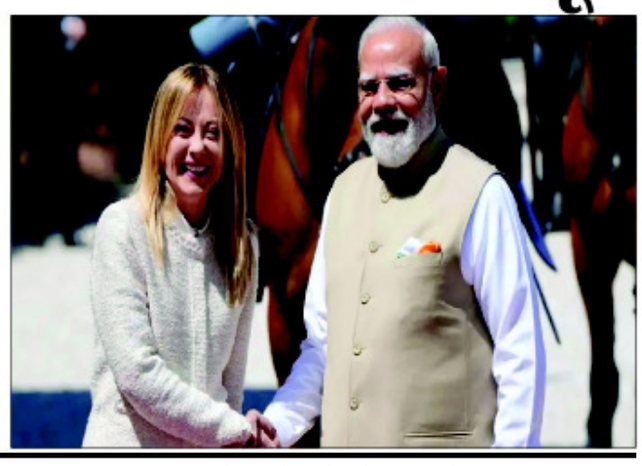

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। RNI No. RAJHIN/2001/05699 मो. नं. 9928078717